अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भूमि का आबंटन

2112. **श्री रामजी लाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लोगों को आवंटित की गई भूमि का कब्जा उन्हें सौंप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत 3 वर्षों के दौरान 28 फरवरी, 1993 तक का राज्यवार और जिला वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और अब तक उपर्युक्त श्रेणियों के कितने लोगों को आबंटित भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है, इस संबंध में राज्यवार और जिलावार आंकड़े क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं और राज्यों को इस दिशा में क्या निर्देश दिये गये हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) राज्य सरकारें यह सूचित करती रही हैं कि पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आबंटित भूमि के कब्जे उन्हें दिलवाये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार इस विषय में जिलावार सूचना की निगरानी नहीं रखती है।

(घ) राज्यों से समय-समय पर मुख्य मंत्रियों और राजस्व मंत्रियों के सम्मेलनों सहित विभिन्न मंचों पर यह अनुरोध किया गया है कि वे उन्हें आबंटित भूमि के वास्तविक रूप में कब्जे को सुनिश्चित करें ।

Supply of drinking water to the villages of Bihar

2113. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware that in the villages of famine hit Bihar due to severe drought conditions the main sources of drinking water namely wells have either dried out or left with little water resulting in acute shortage of drinking water in the villages;

(b) if so, what action Government have taken to provide drinking water in the villages in the State;

(c) whether Government have allocated special funds to the State for digging additional wells in every village of the State;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, what action Government propose to take to make drinking water available to the helpless population of Bihar?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) The Central Team which had visited Bihar in October, 1992 had reported that a large number of handpumps require rejuvenation/relocation in the drought affected areas to overcome the drinking water problem of the affected villages.

(b) The problem of drinking water in villages affected due to drought/scarcity conditions is tackled by utilising the annual allocated amount of Rs. 35 crores under the Calamity Relief Fund of which the Centre's contribution is Rs. 26.25 crores. In addition, normal Plan funds under rural water supply programme can also be entailed to achieve the objective. The State Govrnmnt's proposal for permitting utilisation of 30 per cent of Accelerated Rural Water